एआई ने 90 साल पुरानी पहेली 88 घंटे में सुलझाई

कमाल

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। ओपनएआई ने दावा किया है कि उसने 90 साल से इंसानों के लिए पहेली बने गणित के सवाल का जवाब खोज निकाला है। दावा है कि नए एआई मॉडल और 10 हजार एआई एजेंट्स ने 88 घंटे में हल कर दिया। जिस पहेली को हल किया गया वह नेवियर-स्टोक्स समीकरण से जुड़ी है। यह इस बात को समझाने में मदद करती है कि पानी, हवा और दूसरे तरल पदार्थ कैसे बहते हैं।



30 लाख संदेशों का आदान-प्रदान किया

130 अरब आउटपुट टोकन प्रयोग किए

समाधान को खोजने में 17 घंटे लगे

एआई ने पहेली का समाधान करते हुए पता लगाया कि कुछ खास परिस्थितियों में इस गणितीय मॉडल में तरल की गति एक निश्चित समय पर अनंत हो जाती है। समस्या पर काम करते हुए हजारों एआई एजेंट्स ने आपस में लगभग 30 लाख संदेशों का आदान-प्रदान किया। करीब 130 अरब आउटपुट टोकन इस्तेमाल किए। कंपनी के जीपीटी-6 एस्ट्रा मॉडल ने समाधान को जांचने में करीब 17 घंटे लगाए।

क्या थी अनसुलझी गणितीय पहेली

नेवियर-स्टोक्स समीकरण यह समझने में मदद करता है कि पानी, हवा और दूसरे तरल पदार्थ कैसे बहते हैं। इनका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, विमान के डिजाइन, समुद्र और नदियों के पानी के अध्ययन और यहां तक कि खून के शरीर में बहने को समझने में भी किया जाता है। हालांकि, एक सवाल अनसुलझा रहा कि क्या यह समीकरण हर स्थिति में ठीक तरह से काम करता है। क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने 2000 में इसे सात 'मिलेनियम प्रॉब्लम्स' में शामिल किया था। हर समस्या सुलझाने पर 10 लाख डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

क्या होते हैं एआई एजेंट्स

- ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो एआई की मदद से किसी काम को खुद कर सकते हैं।
- हर एजेंट समस्या को अलग तरीके से हल खोजने में मदद करते हैं।
- एआई बॉट ऐसे प्रोग्राम हैं जो निर्देश के अनुसार काम करते हैं। जैसे ग्राहक सेवा का बॉट सवाल का जवाब देता है।

ओपनएआई के दावे पर छिड़ा विवाद

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर ट्रिस्टन बकमास्टर और एंथ्रोपिक से जुड़े गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे भी नेवियर-स्टोक्स की गुत्थी पर काम कर रहे थे। दोनों अपने शोध में ओपनएआई के कोडेक्स टूल का भी प्रयोग कर रहे थे। बकमास्टर का कहना है कि 3 सितंबर को उन्हें पता चला कि उनके शोध की प्रगति से जुड़ी जानकारी ओपनएआई तक पहुंच गई है। कुछ दिनों बाद कंपनी ने गुत्थी सुलझाने का दावा कर दिया। दूसरी तरफ, ओपनएआई ने आरोपों को खारिज कर दिया।

10 हजार इंसान लगते तो..

अगर 10 हजार इंसान एक साथ इस पहेली को सुलझाने पर काम करते तो, जरूरी नहीं कि समस्या जल्दी हल हो जाती। हर व्यक्ति को समस्या समझने, नए विचार देने, गणना करने और दूसरे लोगों के काम की जांच करने में समय लगता। ड़ी मुश्किल तालमेल की होती।

विशेषज्ञ ने चेताया, एआई इंसान को खत्म कर देगा

चिंता

- एआई के खतरे को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा
- एजैकब कॉक्सन ने कहा जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। एंथ्रोपिक के एआई शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया।

एआई के कारण तेजी से हो रहे बदलाव पर चेतावनी देते हुए 27 वर्षीय जैकब ने कहा कि ओपनएआई समेत टेक्नोलॉजी कंपनियां सुपरइंटेलिजेंस विकसित करने की अंधी दौड़ में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही हैं और इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। विशेषज्ञ ने चेताया, एआई इनसान को खत्म कर देगा। दरअसल, कॉक्सन पिछले तीन साल ओपनएआई और एंथ्रोपिक दोनों में प्री-ट्रेनिंग रिसर्च में बिताए हैं। दोनों कंपनियों के बीच एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना आगे बढ़ रही है।

सिस्टम में सेंध लगने का खतरा : एआई के गंभीर खतरे को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा है। प्रौद्योगिकी तेजी से ऐसे मानव से अधिक सक्षम एआई सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जो किसी भी प्रणाली में सेंध लगा सकते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति दिसानायके ने दिया भरोसा

भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा श्रीलंका

आश्वासन

कोलंबो, एजेंसी। जनाथ सिंह ने बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बैठक में दिसानायके ने आश्वासन दिया कि श्रीलंका कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने पर भी वार्ता हुई। साथ ही समुद्री संबंधों को और गहरा करने के लिए तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए।

2017 में कर्ज न चुका पाने से श्रीलंका को रणनीतिक हंबनटोटा बंदरगाह और उसके आसपास की 15 हजार एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर चीन को सौंपनी पड़ी थी। राजनाथ ने कहा, श्रीलंका के सबसे करीबी दोस्त होने के नाते भारत 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में काम करने को एहसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूर्या से भी मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।



कोलंबो में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। ● प्रेट्र

इन समझौतों पर हस्ताक्षर

दोनों देशों ने श्रीलंकाई वायु सेना के लिए एल70 गन को अपग्रेड करने, दोनों देशों के एनसीसी और नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के बीच सहयोग के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए। इससे एयर डिफेंस व्यवस्था काफी मजबूत होगी।

हिंद महासागर में साझा निगरानी प्रणाली बने : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षित समुद्री मार्ग, स्वतंत्र नौवहन, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और निर्बाध समुद्री व्यापार दक्षिण एशिया की वृद्धि के लिए जरूरी हैं। दोनों देशों के बंदरगाह साझा आर्थिक विकास के इंजन बन सकते हैं। राजनाथ सिंह ने अवैध मछली पकड़ने, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद रोकने के लिए वास्तविक समय में सूचना साझा करने वाली एकीकृत समुद्री प्रणाली विकसित करने की जरूरत बताई। साथ ही, उन्होंने 'महासागर' विजन के तहत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड कानून के दायरे से बाहर क्यों: कोर्ट

अदालत से

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) और प्रदेश क्रिकेट संघों से पूछा है कि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के दायरे में क्यो नहीं आ सकते।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को बीसीसीआई के मामले में कुछ क्रिकेट ईकाइयों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। पीठ ने बीसीसीआई और प्रदेश संघों के वकीलों से यह भी कहा कि वे इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें 2025 के उस अधिनियम के तहत क्यो नहीं आनी चाहिए जो अब लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2014 में दायर बीसीसीआई से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है और समय-समय पर इस मामले में कई आवेदन दाखिल हो चुके हैं।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने सुधार के उपाय सुझाने के लिए पूर्व सीजेआई जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति को दी गई जिम्मेदारियों में बीसीसीआई के लिए संविधान तैयार करना भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के ढांचे, संगठन और कामकाज में सुधार से जुड़ी समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया था।

न्यायपालिका आलोचना के खिलाफ नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका आलोचना के खिलाफ नहीं है और न ही हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसी आलोचना सही मंच पर और निष्पक्ष व तर्कसंगत तरीके से की जानी चाहिए। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब की, जब वे कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के ज़िक्र से जुड़ी स्वत: संज्ञान वाली कार्यवाही को बंद कर रहे थे। फर्क जिम्मेदार बातचीत और बिना जानकारी के किए गए दावों के बीच है।

केयर्न इंडिया संबंधी मामला सैट को लौटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शेयरों की पुनर्खरीद को लेकर 2014 में की गई भ्रामक घोषणा के मामले में केयर्न इंडिया पर बाजार नियामक सेबी द्वारा लगाए गए 5.25 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा मामला प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) को वापस भेज दिया। पीठ ने कहा कि कारोबार संबंधी आंकड़ों में मौजूद विरोधाभासों की जांच करना और यह तय करना कि दोनों सैट के अधिकार क्षेत्र में आता है।



देश-विदेश 30 S

आयोग के समक्ष मेटा के अधिकारी पेश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री के विज्ञापनों के मामले में मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक और प्रमुख को बुधवार को तलब कर पूछताछ की। आयोग ने तीन जुलाई को एक खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए मेटा के अफसरों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। आयोग ने मेटा प्लेटफार्म्स इंक से स्पष्टीकरण मांगा था। मेटा ने एक सप्ताह बाद आयोग को अपना जवाब सौंपा था।

ईरान-अमेरिका ने एक दूसरे पर ड्रोन से हमला बोला

वाशिंगटन। करीब एक हफ्ते की शांति के बाद मंगलवार देर रात अमेरिका-ईरान में संघर्ष फिर भड़क गया। दोनों ने एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले किए। अमेरिकी हमलों में तेहरान के पांच तेल पोत नष्ट हो गए। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान द्वारा बीते दो दिनों में उसके युद्धपोत पर दो बार मिसाइल हमले की कोशिश की गई।

मेटा ने पुलकित मणि की इंस्टा रील्स बहाल की



नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि की तरफ से कॉपीराइट शिकायतों के आधार पर इंस्टाग्राम से हटाई गईं दो रील्स बहाल कर दी गई है। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दोनों रील्स के संबंधित लिंक बहाल कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में रहने वाले पुलकित मणि मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

अजीत भारती जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीत भारती ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला भारती द्वारा चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सत्र अदालत ने सात सितंबर को भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब 80% पौधरोपण जरूरी

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए पेड़ लगाने के नियमों को और सख्त कर दिया है। नए दिशानिर्देशों के तहत अब 80 प्रतिशत क्षेत्र में पौधरोपण और 90 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने को अनिवार्य किया है। वहीं राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना है। कहा गया कि पहले परियोजनाओं के लिए पौधरोपण दायित्वों को उचित महत्व नहीं दिया जाता था।

बांग्लादेश के चटगांव में बुधवार को युद्धाभ्यास के दौरान चीन निर्मित टैंक में विस्फोट हो गया। इससे दो सैनिकों की मौत हो गई। इसका वीडियो वायरल हुआ। ● वीडियो ग्रैब

बांग्लादेश से रक्षा संबंध चाहता है भारत : त्रिवेदी

ढाका। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बुधवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) शम्सुल इस्लाम से मुलाकात की। छावनी स्थित कार्यालय में त्रिवेदी ने कहा, ढाका के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंधों को भारत बहुत महत्व देता है। उच्चायुक्त ने पेशेवर सहयोग और साझा सुरक्षा हितों के क्षेत्र में बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के साथ काम करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

परियोजनाओं में गुणवत्ता को लेकर गडकरी सख्त

पणजी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं में देरी और घटिया निर्माण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह जिम्मेदार ठेकेदारों को अधिकतम संख्या में ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। गडकरी ने पणजी के पास पोरवोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

पाक को दो टूक, काबुल में नहीं है मसूद अजहर

नई दिल्ली। तालिबान सरकार ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के अफगानिस्तान में सक्रिय होने के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अजहर उनके देश में नहीं है।

भारत रत्न प्रोफेसर राव को नोटिस मिलने पर विवाद

- बेंगलुरु प्राधिकरण ने कहा कि नाम विसंगति पर नोटिस नहीं दिया

बेंगलुरु, एजेंसी। भारत रत्न से सम्मानित और मशहूर वैज्ञानिक 92 वर्षीय प्रोफेसर सीएन आर राव को कर्नाटक में चल रही मतदाता सूची की एसआईआर के तहत एक नोटिस मिला। यह नोटिस उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर के कारण भेजा गया था। इसको लेकर हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी उनके घर जाकर सत्यापन करेंगे।

वहीं ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने कहा कि राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम प्रोफेसर सीएनआर राव है, जबकि मौजूदा वोटर लिस्ट में उनके प्रोफेशनल टाइटल में एक अतिरिक्त एफ है।

92 वर्षीय वैज्ञानिक को जारी हुए इस नोटिस में प्रोफेसर राव को इस विसंगति को दूर करने के लिए सुनवाई में हाजिर होने और सफाई देने को कहा गया है।

नोटिस नहीं दिया: ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त एम महेश्वर राव ने बुधवार को कहा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रो. सीएनआर राव को नाम में विसंगति को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। मतदाता सूची में संबंधित व्यक्ति के नाम में कुछ विसंगति पाई गई थी।

संघ दफ्तर पर हमले में एनआईए के छापे

पटना, हिब्यू। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पटना में छापेमारी की। यह छापेमारी कंकड़बाग मेन रोड स्थित साईं कुसुम इनफिनिटी अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में की गयी।

सूत्रों के मुताबिक, यह दोनों फ्लैट नंबर 1206 और 609 संदीप कुमार के नाम से खरीदे गये हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान फ्लैट का दरवाजा बंद था। छापेमारी टीम ने दरवाजा तोड़ कर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये गये हैं। एनआईए की टीम के साथ बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आठ सदस्यीय टीम पहुंची थी।

जब वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं तो पति पर मुकदमा कैसे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब 'वैवाहिक दुष्कर्म' को दुष्कर्म का अपराध नहीं मानने का कानून अभी मौजूद है तो पति के खिलाफ पत्नी से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है?

अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले के संदर्भ में यह सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून में मौजूद अपवाद पूरी तरह लागू नहीं होता। जो पति अपनी पत्नी से बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है, उस पर रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने आईपीसी और उसकी जगह लेने वाले बीएनएस में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने सवालिया लहजे में कहा 'क्या अदालत किसी पति पर अपनी पत्नी से दुष्कर्म का मुकदमा चला सकता है, जबकि इस छूट की संवैधानिक वैधता पर अभी फैसला आना बाकी है। जस्टिस बागची ने कहा जब तक हम इस अपवाद (वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान) की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं ले लेते, क्या पति के खिलाफ पत्नी से दुष्कर्म का मुकदमा चलाने की इजाजत दी जा सकती है?

कानून में क्या है प्रावधान

आईपीसी की धारा 375 के अपवाद -2 के तहत यदि कोई विवाहित पुरुष बालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। नए कानून बीएनएस की धारा 63 रेप का अपवाद-2 कहता है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी बालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन क्रिया करना दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जाएगा।

मंत्री, सांसद बेटी के ठिकानों पर छापे

बेंगलुरु। ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी एवं कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली और कुछ अन्य से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 18 परिसरों की तलाशी ली गई। इनमें सतीश जारकीहोली का शहर के डॉलर्स कॉलोनी इलाके में स्थित परिसर, उनकी बेटी प्रियंका के परिसर और बेलगावी में उनके बहनोई वाई. डी. मंजूनाथ से जुड़े परिसर शामिल हैं।

ब्रिक्स ने पहचान बनाई पर लंबा रास्ता बाकी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर)

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह अपने उद्देश्यों में सफल हुआ या नहीं। इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स ने पहचान तो बनाई है, लेकिन लक्ष्य से अब भी दूर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रिक्स को मजबूती, एकता के साथ निडर होकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुधीर सिंह ने कहा कि शीत युद्ध के बाद दुनिया पर पश्चिम का खासकर अमेरिका का दबदबा कायम होता गया। जहां विकासशील और गरीब देशों की कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसे में ब्रिक्स की स्थापना महत्वपूर्ण कदम था। इस मंच पर भारत, रूस, ब्राजील और चीन जैसे तेजी से आगे बढ़ते देश एकत्र हुए, जिसका परोक्ष मकसद पश्चिम के एकाधिकार को चुनौती देना था।

सिंह कहते हैं कि इन 20 सालों में ब्रिक्स पश्चिम के वर्चस्व को तोड़ने में भले ही विफल रहा है, लेकिन एक मंच के रूप में अपनी पहचान कायम की है। दुनिया आज इस मंच की ओर देख रही है। इसलिए उसका लगातार विस्तार भी हो रहा है।

ब्रिटेन से बाहर जाने की इजाजत नहीं : माल्या

लंदन, एजेंसी। कारोबारी विजय माल्या ने खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा किया कि उसे कानूनी तौर पर ब्रिटेन छोड़ने से रोका गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में माल्या ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है।

दरअसल, विजय माल्या का यह बयान केंद्र सरकार के उन आंकड़ों के बाद आया है, जिसमें अक्तूबर, 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत 15 व्यक्तियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। इसमें विजय माल्या और नीरव मोदी शामिल हैं। माल्या ने एक्स पर लिखा, जो लोग मुझे भगोड़ा कहते हैं, वे ध्यान दें कि मैं 1992 से ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं और मुझे कानूनी रूप से यह देश छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया है।

सीट बेल्ट पर पर्याप्त कानून : शीर्ष अदालत

सुनवाई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य बनाने वाले मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और इनका पालन सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

शीर्ष अदालत ने गाड़ी चलाने के दौरान वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि सीट बेल्ट को लेकर कानून बहुत साफ है। सवाल इसके लागू होने का है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश का हर नागरिक और हर चालक इसका पालन करे?

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों द्वारा कानून का पालन नहीं करना या कानून लागू करने वाली एजेंसियों का नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं कर पाना, असल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति संबंधित प्राधिकार को भेजने की अनुमति दे दी, ताकि अधिकारी उसके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर सकें। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले पर अपने सुझाव भी सक्षम प्राधिकार को भेजे।



दलील : सड़क हादसों में होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत की पीठ से कहा कि यदि सीट बेल्ट पहनने के नियम का पालन किया जाए, तो सड़क हादसों में होने वाली कई मौतों और चोटों को रोका जा सकता है। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि कानून के बावजूद, फैंसी सीट कवर या अन्य बदलावों की वजह से कई गाड़ियों में सीट बेल्ट काम नहीं करती। याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि लोगों की लापरवाही और कानून का कमजोर क्रियान्वयन देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों और यहां तक कि मौतों का कारण बनता है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा: प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन, पीडीआर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी 221010 (यू.पी.)
E-mail: sarvar@bankofbaroda.com, website: www.bankofbaroda.bank.in, Mob. 9554959534

विक्रय सूचना
अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु
अनुलग्नक - IV-A
{(नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें)}

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-निलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी/जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है, जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई नीलामी/बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता/कानूनी वारिस/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ई.एम.डी.) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

नीलामी की तिथि 22.10.2026 समय दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 21.10.2026 या उसके पहले किया जायेगा।

क्र. स.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता/कानूनी वारिसों/ प्रोपराइटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया धनराशि	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
1.	ऋणकर्ता: मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेज पंजीकृत पता: एस 19/141 ए-21-के.ए., जदीद बाजार, नदेसर, वाराणसी (उ.प्र.) - 221002, प्रोपराइटर: श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री अरुण कुमार पता: मकान नं. 144 ग्राम बेन पोस्ट बेन तियरी, चंदौली (उ.प्र.) - 232103 जमानतकर्ता : श्री चंद्र शेखर पाल पुत्र श्री मोहन, पता: ग्राम बेन पोस्ट बेन तियरी जिला चंदौली (उ.प्र.) - 232103	अचल संपत्ति के सभी भाग व खंड जिसमें आवासीय भूमि व भवन, आराजी नं.- 570 मि., क्षेत्रफल- 1833.12 वर्ग फीट, मौजा- बेन, परगना- कैरमंगरौर, तहसील- चकिया, जिला- चंदौली, श्री चंद्रशेखर पाल पुत्र श्री मोहन के नाम पर है। चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार: पूर्व: चकिया से इलिया रोड, पश्चिम: चंद्रशेखर की भूमि, उत्तर: गिरजा साव का मकान, दक्षिण: रामचंद्र पाल का मकान	₹ 32,79,780.67/- + 10.05.2025 से ब्याज और अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	Rs. 52,00,000/- (आरक्षित धनराशि) 5,20,000/- (अग्रिम धनराशि) 25,000/- (बिड बढ़ोत्तरी धनराशि)	सांकेतिक कब्जा	21.10.2026 समय 02:00 PM से 05:00 PM

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें- www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं. 9554959534, ईमेल: sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांकित: 07.09.2026 स्थान: वाराणसी ह/० प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

https://rktv.live/p/epaper.html